

55  
17.1.72



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं० 554] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 10, 1971/कार्तिक 19, 1893

No. 554] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 1971/KARTIKA 19, 1893

---

इस भाग में भिन्नपृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation.

---

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

ORDERS

New Delhi, the 10th November 1971

S.O. 5141.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Jaduguda Uranium Mine of Messrs Uranium Corporation of India Limited, Post Office Jaduguda Mines, District Singhbhum and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

(3097)

## SCHEDULE

"Whether the demands of workmen of Jaduguda mines of Messrs Uranium Corporation of India Limited, Post Office Jaduguda Mines, District Singhbhum in respect of the following are justified? If so, to what relief are they entitled?

- (i) Grant of Medical benefits;
- (ii) Regularisation of casual workmen."

[No. L-29011/44/71-LR-IV.]

**श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय**  
( श्रम और रोजगार विभाग )

आदेश

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1971

का० प्रा० 5141.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विविष्ट विषयों के बारे में मैसर्स युरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की जादुगूदा युरेनियम माइन, डाकघर जादुगूदा माइन्स, जिला सिंहभूम के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उत के कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है।

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब औद्योगिक विकास अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (संख्या 2), धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

**अनुसूची**

"क्या मैसर्स युरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की जादुगूदा माइन्स, डाकघर जादुगूदा माइन्स, जिला सिंहभूम के कर्मचारों की निम्नलिखित के सम्बन्ध में मांगें न्यायोचित हैं? यदि हां, तो वे किस अनुतोष के हकदार हैं?

- (i) चिकित्सा लाभ देना ;
- (ii) अनियत कर्मचारों का नियमितकरण "

[सं० एल० 29011/44/71/-एल० आर०-4]

S.O. 5142.—Whereas by an order of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. L-29011/44/71-LR-IV, dated the 10th November, 1971, an industrial dispute between the employers in relation to the management of Jaduguda Uranium Mine of Messrs Uranium Corporation of India Limited, and their workmen has been referred to the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad, for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of the section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby prohibits the continuance of the strike in existence in the said establishment in connection with the said dispute.

[No. L-29011/44/71-LR-IV.]

BALWANT SINGH, Under Secy.

सा० आ० 4251.—यतः भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) के आदेश संख्या एल-29011/44/71-एल० आर०-4, तारीख 10 नवम्बर, 1971 द्वारा मैसर्स युरेनियम कारपोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड की जादुगूदा युरेनियम माइन के प्रबन्ध से सम्बन्ध नियोजकों और उन के कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (संख्या 2), धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्दिष्ट किया गया है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त स्थापन में उक्त विवाद के सम्बन्ध में विद्यमान हड़ताल के जारी रहने को एतद्द्वारा प्रतिनिषिद्ध करती है।

[संख्या एल०-29011/44/71-एल० आर०-4]

बलवन्त सिंह, अवसर सचिव।

